been done of Mahbabnagar, Ronga Reddy and Nalgonda District of Andhra Pradesh;

(c) if so, details thereof; and

(d) whether C. G. W. B. has contacted the Government of Andhra Pradesh in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir. The Central Ground Water Board in consultation with the State Governments has provisionally and tentatively reassessed the utilisable ground water resources of the country as 45.23 million hectare metre (m.ha. m). as compared to earlier estimates of 26.7 m.ha.m. worked out in 1972.

(b) and (c) The Grond Water Resources of Andhra Pradesh have been provisionally and tentatively reassessed as 3.34 m. ha.m. as compared to earlier estimate of 2.12 m.ha. m. of 1972. The provisionally and tentatively reassessed ground water resources in respect of Mehboobnagar, Ranga Reddy and Nalgonda districts are 0.15, 0.07 and 0.17 m. ha. m. respectively.

(d) Yes, Sir.

मध्य प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये विदेशी वित्तीय सहायता

2250. **श्री अजीत जोगी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता से शुरु की जाने वाली बाढ़ नियंत्रण संबंधी मध्य प्रदेश सरकार की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या विदेशी सहायता योजना के अंतर्गत आने वाली नर्मदा तथा चुनाब नदियों संबंधी बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की कोई मांग है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

लघु सिंचाई के अंतर्गत लाई गई भूमि

2251. **श्री अजीत जोगी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1992 के अंत तक राज्यवार कितनी भूमि लघु-सिंचाई के अंतर्गत लाई गई है ;

(ख) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार सिंचाई क्षमता कितनी है ;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में लघु सिंचाई के अंतर्गत अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिये राज्यवार निर्धारित किये गये लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है : और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्षमता : हजार हेक्टे0 में

परिव्यय करोड़ रुपए में

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित का नाम	वर्ष 1991–92 के अंत तक सृजित लघु सिंचाई क्षमता	चरम लघु सिंचाई क्षमता (अनन्तिम आंकलन)	आठवीं योजना के दौरान अतिरिक्त सिंचाई लघु क्षमता सृजित करने के लिए लक्ष्य	आठवीं योजना के दौरान लघु सिंचाई के लिए योजना
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	2877.34	7490	500	234.68
2	अरुणाचल प्रदेश	64.89	170	20	53.69
3	असम	575.28	2440	180	183.45
4	बिहार	4876.90	7400	1832	1021.30
5.	गोआ	18.41	105	4	13.10
6	गुजरात	1900.30	5175	180	240.00
7	हरियाणा	1524.47	1930	100	134.45
8	हिमाचल प्रदेश	141.61	305	25	95.25
9	जम्मू और कश्मीर	363.62	1180	40	84.20
10	कर्नाटक	1435.48	4020	220	306.91
11.	केरल	518.04	1780	100	130.00
12	मध्य प्रदेश	2560.52	14900	500	728.37
13	महाराष्ट्र	2457.40	7040	400	612.17
14	मणीपुर	49.57	510	15	25.00
15	मेघालय	42.51	245	12	29.03
16	मिजोरम	10.54	70	6	11.75
17	नागालैंड	65.10	5	13	21.00

1	2	3	4	5	6
18	उड़ीसा	1245.38	6400	150	389.40
19	पंजाब	3290.45	3870	76	113.20
20	राजस्थान	2388.71	3420	300	171.92
21	सिक्किम	22.19	50	5	11.50
22	तमिलनाडु	2107.91	4350	110	250.00
23	त्रिपुरा	87.38	440	27	31.50
24	उत्तर प्रदेश	18870.00	21200	5439	400.60
25	पश्चिम बंगाल	2772.37	3180	450	370.00
	कुल राज्य	50266.37	97727	10704	5662.47
	संघ राज्य क्षेत्र	81.89	101	7	21.79
	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	50348.26	97828	10711	5684.26
	केन्द्रीय क्षेत्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	293.00
	कुल योग	50348.26	97828	10711	5977.26

Guidelines to control the growth of cities

2252. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether any guidelines are proposed to be issued to different States to control the growth of large cities;

(b) whether in view of rapid urbanisation, a specialised cadre of offices for corporation and Municipalities is also likely to be formed; and

(c) what administrative steps are to be taken to give urban areas better administration all over the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Urban Development is a state subject and policies to control (or promote) the growth of cities/towns are pursued by State Governments. Therefor, no formal guidelines are proposed to be issued to different states to control the growth of large cities. However, while assisting State Governments through centrally sponsored schemes such as Integrated Development of Small and Medium Towns (IDSMT) Ministry of Urban Development insists on preparation of Urban Development Strategy Papers by State Governments, parti-